भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
लेखापरीक्षा, बजट व समन्वयन कक्ष / Audit, Budget & Co-ordination Cell
मानव संसाधन प्रबंध विभाग / Human Resource Management Department
तिरुवनंतपुरम / Thiruvananthapuram

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त – भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम द्वारा 01 अक्तूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

उपर्युक्त निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 अगस्त 2024 को प्रातः 11:00 बजे आरबीआई मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम की दूसरी मंजिल पर स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची नीचे दी गई है:

(क) बैठक में भाग लेने वाले बैंक अधिकारियों की सूची

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	श्रीमती सुजाता जे	महाप्रबंधक
2	श्री सवियो जोस वानियापुरा	प्रबंधक
3	श्री एम मुत्तुराजा	सहायक प्रबंधक
4	श्री शरन चंद्रन	सहायक
5	श्री राहुल आर नायर	सहायक

(ख) बैठक में भाग लेने वाले सनदी लेखा फर्म प्रतिनिधियों के नाम

क्रम सं.	प्रतिनिधि का नाम	फर्म का नाम
1	श्री कृष्णतन एन	वर्मा और वर्मा
2	श्री सजीव सैमुअल	बालन रेनजी एंड एसोसिएट्स
3	अमिता वर्गीस	एसवीआरएल एंड कंपनी
4	रिंदा ई जे	

2. बैठक की अध्यक्षता श्रीमती सुजाता जगन्नाथन श्रीमती सुजाता जगन्नाथन महाप्रबंधक, मासंप्रवि ने की। श्री सवियो जोस वनियापुरा, प्रबंधक ने बैठक में प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसके बाद, प्रतिभागियों से उक्त निविदा के संबंध में कोई प्रश्न, यदि कोई हो, आमंत्रित किए गए। प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और बैंक के स्पष्टीकरण का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	प्रश्न	बैंक का स्पष्टीकरण
a	पृष्ठ 26 के संदर्भ में, बिंदु (xii) में कहा गया है कि "फर्म बैंक के जीएसटी और आयकर रिटर्न (और कोई अन्य संबंधित रिटर्न/रिटर्न जो बाद में लागू हो सकते हैं) को निर्धारित	यह स्पष्ट किया गया कि आरबीआई रिटर्न तैयार करके दाखिल करेगा। फर्म को भुगतान से पहले और भुगतान के बाद लागू किए गए और काटे गए करों की शुद्धता का सत्यापन करना

	अंतराल पर तैयार और दाखिल करेगी।" क्या फर्म दाखिल करने के लिए ज़िम्मेदार होगी या दाखिल करने से पहले केवल रिटर्न की जांच करेगी।	आवश्यक है। लेखापरीक्षक यह भी सत्यापित करेंगे कि रिटर्न सही तरीके से दाखिल किए गए हैं। तदनुसार, यह पंक्ति इस प्रकार पढ़ी जा सकती है "फर्म पूर्व-भुगतान (मंजूरी के बाद) और भुगतान के बाद के चरणों में प्राप्त और काटे गए करों की सत्यता की समीक्षा और सत्यापन करेगी। फर्म निर्दिष्ट अंतराल पर दाखिल करने से पहले बैंक के जीएसटी और आयकर रिटर्न (और साथ ही अन्य कोई संबंधित रिटर्न/जो बाद में लागू हो सकते हैं) के मसौदों का सत्यापन करेगा और उसके बाद दाखिल किए गए रिटर्न की सत्यता की जांच करेगी।"
b	पृष्ठ 26 के संदर्भ में, बिंदु (xiii) में कहा गया है कि "समवर्ती लेखा परीक्षक को आईटीसी पात्रता, विक्रेता की जीएसटीएन सक्रिय स्थिति और विक्रेता की पैन स्थिति के लिए एचएसएन को सत्यापित करना आवश्यक होगा। विभिन्न कर अधिकारियों से प्राप्त अधिसूचना, यदि कोई हो, के संबंध में अन्य विविध कार्य" फर्मों ने विविध कार्यों पर स्पष्टीकरण मांगा।	'विविध कार्यों' पर यह स्पष्ट दिया गया कि समवर्ती लेखा परीक्षक को समय-समय पर संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अधिसूचित आईटी/जीएसटी दरों/नियमों/कानूनों में परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए। सीए को अपने सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान से पहले और रिटर्न दाखिल करते समय विभागों द्वारा इस संबंध में नवीनतम संशोधन/अधिसूचनाओं का अनुपालन किया जा रहा है। फर्म को वाउचर की अंकगणितीय सटीकता के सत्यापन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

3. फर्मों को यह भी बताया गया कि उन्हें एमएसटीसी पोर्टल में किसी भी अंतिम-मिनट की त्रुटि से बचने के लिए बोली की अंतिम तिथि से पहले निविदा दस्तावेज़ अपलोड करने का प्रयास करना चाहिए। फर्मों को यह भी बताया गया कि सफल निविदाकर्ता के अलावा अन्य सभी निविदाओं की ईएमडी सफल निविदाकर्ता को संविदा दिए जाने पर वापस कर दी जाएगी। फर्मों को यह भी चेतावनी दी गई कि वित्तीय बोली राशि में जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए और विनिर्दिष्ट न्यूनतम बोली (यानी ₹1,00,000 मासिक) से कम की कोई भी बोली अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।

4. बोलीदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि बोली-पूर्व बैठक के दौरान बैंक द्वारा दिए गए उपरोक्त सभी स्पष्टीकरण, निविदा दस्तावेज़ में दर्शाए गए विवरण के साथ, निविदा/संविदा का हिस्सा होंगे।

5. मध्याह्न 12 बजे बैठक समाप्त हुई।

क्षेत्रीय निदेशक

(केरल और लक्षद्वीप)